एम/एस. सुभाष प्रोजेक्ट्स एंड मार्केटिंग लिमिटेड

बनाम

पश्चिम बंगाल विद्युत विकास निगम लि. और अन्य

21 अक्टूबर] 2005

[आर.सी. लाहोटी, सी.जे., जी.पी. माथुर और पी.के. बालासुब्रमण्यन, जे.जे.]

अनुबंध:

निविदाओं का आमंत्रण -मूल्य बोली खोलने से पहले, निविदा सूचना में पाई गई अस्पष्टता के कारण, कुछ विचलन का सुझाव दिया गया - विचलन के आलोक में, निविदाकर्ता नए प्रस्ताव दे रहे हैं - मूल प्रस्ताव में, पहली पार्टी सबसे कम बोली लगाने वाली थी - ताजा पेशकश में, दूसरी पार्टी मूल निविदा राशि को कम करके सबसे कम बोली लगाने वाला बन गया - दूसरे पक्ष का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया - मंत्री के प्रभाव पर, पहले पक्ष को ठेका दे दिया गया - उच्च न्यायालय ने मंत्रालय के प्रभाव को गलत माना, लेकिन पहले पक्ष द्वारा किए गए पर्याप्त काम के रूप में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, हालांकि प्रथम पक्षकार को एक करोड़ रूपये का भुगतान दुसरे पक्षकार को करने के लिए निर्देशित किया गया -

अपील पर, अभिनिर्धारित : चूंकि बोली लगाने वालों को काम के वास्तविक दायरे और परिमाण को समझने पर उस राशि को कम करने की पेशकश की गई थी जो मूल रूप से निविदा नोटिस में अस्पष्टता द्वारा बनाई गई गलतफहमियों के आधार पर पेश की गई थी, यह नहीं कहा जा सकता कि ऐसे प्रस्तावों को अस्वीकार किया जा सकता था, अनुबंध का बड़ा हिस्सा निष्पादित होने के बाद, प्रथम पक्ष को न्यायसंगत राहत प्राप्त करने के लिए

दूसरे पक्ष को 1 करोड़ रुपये का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी ठहराया गया।-इक्विटी

ओईसीएफ की सहायता से बकरेश्वर थर्मल पावर प्रोजेक्ट का निर्माण करने के पावर कॉर्पोरेशन के निर्णय के अनुसार, जल सेवन और संयंत्र जल प्रणाली पैकेज के काम के लिए निविदाएं आमंत्रित की गई। अपीलकर्ता और एलएंडटी सहित पांच बोलीदाताओं ने निविदाएं प्रस्तुत की। निविदाकर्ता तकनीकी रूप से योग्य पाये गये। हालाँकि, यह पाया गया कि निविदाएँ आमंत्रित करने वाले नोटिस में कुछ अस्पष्टता आ गई थी और कुछ कार्यों का दायरा अस्पष्ट या अस्पष्ट बना हुआ था। तकनीकी रूप से योग्य निविदाकारों को चर्चा के लिए बुलाया गया था। अंततः, तकनीकी-व्यावसायिक मूल्यांकन के लिए तकनीकी मूल्यांकन समिति की बैठक में सात संशोधनों/विचलनों का सुझाव देने का निर्णय लिया गया।

सात संशोधनों के संबंध में पावर कॉर्पोरेशन द्वारा जारी संचार के अनुसार, अपीलकर्ता ने एक मजबूत बोली लगाई लेकिन अपनी निविदा राशि बढ़ा दी। एल एंड टी ने सात विचलनों को ध्यान में रखते हुए **35** लाख रूपये की वृद्धि का संकेत दिया, लेकिन स्पष्टीकरण और कार्य के वास्तविक दायरे की उचित समझ को ध्यान में रखते हुए, मूल निविदा राशि **64** करोड़ रु. में की कमी का संकेत दिया गया। इसके बाद मूल्य बोलियां खोली गईं। प्रस्तावित मूल कीमत के अनुसार, एल एंड टी को पांचवें सबसे कम बोली लगाने वाले के रूप में रखा गया था और अपीलकर्ता ने हालांकि मूल निविदा में मूल्य भिन्नता का सहारा लिया था, लेकिन उसे सबसे कम बोली लगाने वाला पाया गया। लेकिन बाद के संचार का जवाब देते समय एल एंड टी द्वारा प्रस्तावित कटौती पर ध्यान देने पर, इसकी बोली सबसे कम पाई गई। इसे देखते हुए, निविदा मूल्यांकन समिति, पावर कॉरपोरेशन और ओईसीएफ ने एल एंड टी को अनुबंध देने का फैसला किया। इस स्तर पर, अपीलकर्ता ने केंद्र सरकार में बिजली राज्य मंत्री को एक पत्र लिखा, जिसमें शिकायत की गई कि सबसे कम निविदाकर्ता के रूप में एल एंड टी द्वारा रुपये की कटौती की स्वीकृति, इसकी मूल बोली से **64** करोड़ रुपये निविदा शर्तों के विरुद्ध थी, इस तथ्य को ध्यान में रखते उचित नहीं थी और

बयाना जमा कवर और तकनीकी-वाणिज्यिक मूल्यांकन प्रस्ताव खोले जाने के बाद इस तरह के किसी भी विचलन की अनुमति नहीं दी जा सकती थी, भले ही मूल्य बोलियां स्वयं नहीं खोली गई थीं। इस पत्र के आधार पर पावर कॉर्पोरेशन से कहा गया अपीलकर्ता की शिकायत पर गौर करें. जब पावर कॉर्पोरेशन अपनी स्थिति पर अड़ा रहा और पश्चिम बंगाल सरकार भी इस बात पर सहमत हो गई कि ठेका एलएंडटी को दिया जाएगा, तो बिजली राज्य मंत्री और उनका मंत्रालय इसके आधार पर नए सिरे से मूल्यांकन करने की मांग पर अड़े रहे। मूल बोलियाँ. अंततः, एलएंडटी द्वारा प्रस्तावित **64** करोड़ रुपये की कटौती और अपीलकर्ता को अनुबंध देने की अनदेखी करते हुए एक नया मूल्यांकन किया गया। पीड़ित एलएंडटी ने रिट याचिका के साथ उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। अनुबंध के कामकाज पर कोई रोक नहीं लगाई गई थी, लेकिन उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता को काम जारी रखने की अनुमति दी, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि रिट याचिका की अनुमति होने की स्थिति में वह किसी भी इक्विटी का दावा करने का हकदार नहीं होगा। इस प्रकार, रिट याचिका लंबित रहने पर अपीलकर्ता ने काम का एक हिस्सा पूरा किया।

एकल न्यायाधीश ने माना कि यद्यपि पावर कॉरपोरेशन को बिजली राज्य मंत्री के दबाव के आगे नहीं झुकना चाहिए था और अपीलकर्ता को ठेका नहीं देना चाहिए था, लेकिन विशिष्ट परिस्थितियों में ठेका देने में हस्तक्षेप करना आवश्यक नहीं था। मामला चूँकि अपीलकर्ता द्वारा कार्य का एक भाग पहले ही किया जा चुका था। डिवीजन बेंच ने एकल न्यायाधीश के आदेश की पुष्टि की और आगे कहा कि अपीलकर्ता जिसने संदिग्ध तरीकों से अनुबंध हासिल किया था, वह अनुबंध पर काम करने से अर्जित लाभ का कम से कम एक हिस्सा देने के लिए मजबूर होने के लिए उत्तरदायी था। डिवीजन बेंच ने इसका मूल्यांकन एक करोड़ रुपये के रूप में किया गया जो कि अपीलकर्ता द्वारा अर्जित लाभ के **10** प्रतिशत से कम था और उसने एल एंड टी को इसका भुगतान करने का निर्देश दिया। डिवीजन बेंच के फैसले को अपीलकर्ता, एल एंड टी, यूनियन ऑफ इंडिया, निदेशक **(**थर्मल**)** विद्युत मंत्रालय और केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने चुनौती दी थी।

कोर्ट ने अपील खारिज करते हुए अभिनिर्धारित

अभिनिर्धारित : **1.1.** निविदाएं आमंत्रित करने के लिए नोटिस जारी करते समय पावर कॉर्पोरेशन ने यह स्पष्ट नहीं किया था कि टेंडर किए जाने वाले कार्य का दायरा और सीमा क्या है। निविदाकारों द्वारा प्रस्ताव दिये गये थे। काफी भ्रम था और काम के दायरे और अन्य तकनीकी विवरणों को स्पष्ट करने के लिए स्पष्टीकरण बैठकें और सम्मेलन आयोजित करने पड़े। अंततः सात विचलन भी लिखित रूप में प्रस्तावित किये गये और उन सात भिन्नताओं के आधार पर बोलीदाताओं के प्रस्ताव आमंत्रित किये गये। इसलिए, यह एक ऐसा मामला था जहां काफी भ्रम की स्थिति बनी रही और अपीलकर्ता सहित बोलीदाताओं को मूल्य भिन्नता खंड को हटाने सहित नए सिरे से प्रस्ताव देने के लिए मजबूर होना पड़ा। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि जब ये बातचीत चल रही थी तब मूल्य बोलियाँ नहीं खोली गई थीं और निविदाकारों को स्पष्टीकरण के आलोक में और किए गए सात विचलनों के आलोक में संशोधित प्रस्ताव देने का अवसर दिया गया था। उस अर्थ में, बोलियाँ नहीं खोली गईं, क्योंकि संबंधित बोली, मूल्य बोली, अभी भी खोली जानी बाकी है। यदि, उस स्तर पर, निविदाकारों ने कार्य के वास्तविक दायरे और कार्य की विशालता को समझने के बाद, अस्पष्टता द्वारा उत्पन्न भ्रम से उत्पन्न गलत धारणाओं के आधार पर मूल रूप से प्रस्तावित राशि को कम करने की पेशकश की। निविदाएं आमंत्रित करने वाले नोटिस में यह नहीं कहा जा सकता कि ऐसे प्रस्ताव अस्वीकार किए जा सकते हैं। **[385-**बी, सी, डी, ई**]**

1.2. जब अपने स्वयं के सलाहकारों और ओईसीएफ द्वारा नियुक्त स्वतंत्र सलाहकारों से परामर्श करने के बाद और अपनी स्वयं की निविदा मूल्यांकन समिति के मूल्यांकन के आधार पर, पावर कॉरपोरेशन ने एलएंडटी को सबसे कम निविदाकर्ता के रूप में रखा, तो विद्युत राज्य मंत्रालय के पास कोई औचित्य नहीं था। सभी प्रासंगिक तथ्यों से अवगत कराने के बाद ओईसीएफ और केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण से उचित राय प्राप्त किए बिना भी, मामले के तथ्यों पर, उस पहलू पर जोर देना। इन परिस्थितियों में ऊर्जा राज्य मंत्रालय की जिद और उसका तरीका अजीब लगता है। **[385-**एफ, जीजे**]**

1.3. अपीलकर्ता को एक ठोस प्रस्ताव देने का अवसर दिया गया था, जो वास्तव में, निविदा आमंत्रित करने वाले नोटिस की शर्तों पर ऐसा करने के लिए बाध्य था और इसे अनुबंध दिए जाने से पहले, उसे बाद में अपने दृढ़ प्रस्ताव के रूप में उद्धृत

कीमत से भी इसकी कीमत कम करने का अवसर दिया गया था, इसलिए, यह एक ऐसा मामला था जहां किसी भी स्थिति में, सभी निविदाकारों को आमंत्रित किया जाना चाहिए था और सार्वजनिक हित में और परियोजना के हित में उनमें से सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी को स्वीकार करने से पहले अपनी बोलियां कम करने का अवसर दिया जाना चाहिए था। **[385-**एच**; 386-**ए, बी**]**

2.1. उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने पाया कि संबंधित फ़ाइल कभी भी बिजली मंत्री के समक्ष प्रस्तुत नहीं की गई थी और यह दिखाने के लिए कुछ भी नहीं था कि बिजली राज्य मंत्री को ऐसे मामलों में कोई कार्य सौंपा गया था। वास्तव में, डिवीजन बेंच ने पाया कि सार्वजनिक हित को छोड़कर, संबंधित मामला, बिजली राज्य मंत्री के दायरे में भी नहीं हो सकता है। **[386-**ई, एफ**]**

2.2. ऊर्जा राज्य मंत्रालय का ओईसीएफ को दस्तावेजों के संदर्भ में संपूर्ण तथ्यों से अवगत न कराना और तथ्यों तथा मामले की परिस्थितियों के आधार पर सबसे कम निविदा की पहचान के मामले पर कोई रुख अपनाने से पहले उसकी सलाह न लेना उचित नहीं था। जिस तरह से केंद्र सरकार में ऊर्जा राज्य मंत्री ने इस बारे में काम किया, उसके चलते उच्च न्यायालय की टिप्पणियां सामने आईं, जिसकी शिकायत केंद्र सरकार ने अपील में की थी। सामग्रियों के आधार पर, यह नहीं कहा जा सकता कि उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने जो निष्कर्ष निकाला था वह उचित नहीं था। **[386-**जी**]**

2.3. अपनी अपील में एलएंडटी की दलील है कि अपीलकर्ता को ठेका दिए जाने को रद्द कर दिया जाना चाहिए और ठेका एलएंडटी को देने का निर्देश दिया जाना चाहिए या काम के लिए नए सिरे से निविदा आमंत्रित करने का आदेश दिया जाना चाहिए, इस पर विचार नहीं किया जा सकता है। परियोजना की प्रकृति और पहले ही उठाए गए कदमों और इन अपीलों के लंबित रहने के दौरान परियोजना के पूरा होने को देखते हुए, इस तरह के पाठ्यक्रम को अपनाना इन परिस्थितियों में प्रतिकूल होगा। **[387-**जी**]**

मिस. ए. टी ब्रिज पॉल सिंह और अन्य। बनाम गुजरात राज्य, (1984(4 एससीसी)59, संदर्भित.

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 5030/1999

जी.ए. में ए. संख्या 559/97 में कलकत्ता उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 14.7.98 से। 1997 का क्रमांक 3791.

साथ में

सीए। 1999 की संख्या 5031 और 5032।

सलमान खुर्शीद, ए.के. गांगुली, टी.एस. दौबिया, सुशील कुमार जैन, ए.पी. धमिजा, पुनित जैन, राम निवास, एच.डी. थानवी, वी. कृष्णा मुरथी, प्रदीप आर तिवारी, मनीष शर्मा, वी.के. वर्मा, शैल कुमार द्विवेदी, एनपी, एच.के. पुरी, उज्ज्वल बनर्जी, एस.के. पुरी, श्रीमति प्रिया पुरी और वी.एम. चाैहान उपस्थिति दलाेंं के लिए उनके साथ थे।

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया

पी.के. बालासुब्रमण्यन, जे. 1.ये अपीलें कलकत्ता उच्च न्यायालय में मेसर्स लार्सन एंड टुब्रो (संक्षेप में 'एल एंड टी') द्वारा दायर 1997 की रिट याचिका संख्या 886 से उत्पन्न हुई हैं। रिट याचिका में प्रतिवादी क्रमांक 11 मेसर्स सुभाष प्रोजेक्ट्स एंड मार्केटिंग लिमिटेड (संक्षेप में 'सुभाष प्रोजेक्ट्स') प्रतिस्पर्धी प्रतिवादी था। दिनांक 3.10.1997 के निर्णय द्वारा, उच्च न्यायालय के एक विद्वान एकल न्यायाधीश ने रिट याचिका को खारिज कर दिया। इसके बाद रिट याचिकाकर्ता ने डिवीजन बेंच के समक्ष 1997 की अपील

संख्या 559 दायर की। दिनांक 14.7.1998 के फैसले से, डिवीजन बेंच इस निष्कर्ष पर पहुंची कि अपील स्वीकार की जानी चाहिए और रिट याचिकाकर्ता को राहत दी गई। फिर भी, इसने रिट याचिकाकर्ता, उसके समक्ष अपीलकर्ता को पूरी राहत नहीं दी, लेकिन प्रतिवादी, सुभाष प्रोजेक्ट्स को रिट याचिकाकर्ता को 1 करोड़ रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया। यह इस निष्कर्ष पर था कि प्रतिवादी नंबर 1, पश्चिम बंगाल पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (इसके बाद 'पावर कॉरपोरेशन' के रूप में संदर्भित) द्वारा जारी निविदा के आधार पर अनुबंध रिट याचिकाकर्ता-एल एंड टी को दिया जाना चाहिए था। और प्रतिवादी नंबर 11 सुभाष प्रोजेक्ट्स को इसका अवार्ड देना गैरकानूनी था, लेकिन उस स्तर पर कॉन्ट्रैक्ट के अवार्ड को रद्द करना अनुचित था और कम से कम यह किया जाना चाहिए था कि सुभाष प्रोजेक्ट्स को कम से कम कुछ हिस्से को अलग करने का निर्देश दिया जाए। अवैध रूप से दिए गए अनुबंध से उसने जो लाभ कमाया होगा, उसे रिट याचिकाकर्ता-एल एंड टी को मुआवजे के रूप में दिया जाएगा, जिसे अनुबंध दिया जाना चाहिए था। व्यथित महसूस करते हुए, रिट याचिका में प्रतिवादी संख्या 11, सुभाष प्रोजेक्ट्स ने 1999 की सिविल अपील संख्या 5030 दायर की है। रिट याचिकाकर्ता और उच्च न्यायालय के समक्ष अपीलकर्ता मेसर्स लार्सन एंड टुब्रो ने सी.ए. दायर किया है। 1999 की संख्या 5031 में कहा गया है कि उच्च न्यायालय ने पाया कि सुभाष प्रोजेक्ट्स को ठेका देना अवैध था, और इसे एल एंड टी को दिया जाना चाहिए था, उसे आगे बढ़ना चाहिए था और सुभाष को दिए गए ठेके को रद्द कर देना चाहिए था। परियोजनाओं को एल एंड टी को सौंपने का निर्देश देना चाहिए था। भारत संघ, निदेशक (थर्मल), विद्युत मंत्रालय और केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, जो रिट याचिका में प्रतिवादी 8, 9 और 10 थे, ने सिविल याचिका दायर की है 1999 की अपील संख्या 5032 में डिवीजन बेंच के फैसले को चुनौती दी गई है, लेकिन अनिवार्य रूप से शिकायत की गई है, जैसा कि

सुनवाई में खुलासा किया गया, बिजली मंत्रालय और मंत्री के हस्तक्षेप के बारे में तथा सत्ता के लिए राज्य और उनकी अनुपयुक्तता के बारे में उच्च

न्यायालय की डिवीजन बेंच द्वारा की गई टिप्पणियों के बारे में। चूँकि सभी अपीलें एक ही निर्णय से उत्पन्न हुई हैं, इसलिए उनकी सुनवाई एक साथ की गई है।

2. ओवरसीज इकोनॉमिक कॉरपोरेशन फंड, जापान (बाद में 'ओईसीएफ' के रूप में संदर्भित) की सहायता से, पावर कॉरपोरेशन ने बकरेश्वर थर्मल पावर प्रोजेक्ट का निर्माण करने का निर्णय लिया। उस निर्णय के अनुसरण में, पावर कॉर्पोरेशन ने दिनांक 19.7.1995 को एक नोटिस जारी कर बकरेश्वर थर्मल पावर प्रोजेक्ट की इकाइयाँ के 3 x 20 मेगावाट के लिए जल सेवन और संयंत्र जल प्रणाली पैकेज के कार्य के लिए निविदाएं आमंत्रित की गयी। बोली को तीन अलग-अलग लिफाफों में प्रस्तुत करना आवश्यक था, पहले में बयाना राशि जमा, दूसरे में तकनीकी-वाणिज्यिक मूल्यांकन और तीसरे में मूल्य बोली शामिल थी। निविदा सूचना के अनुसार, सुभाष प्रोजेक्ट्स और एलएंडटी सहित पांच बोलीदाताओं ने निविदाएं प्रस्तुत की। बोलीदाताओं को जारी किए गए निर्देशों के अनुसार, बोलीदाताओं को निविदा विनिर्देशों की प्रमुख आवश्यकताओं से विचलित होने की अनुमति नहीं दी जानी थी। यह प्रावधान किया गया था कि उद्धृत मूल्य अनुबंध की पूरी अवधि के दौरान स्थिर रहना चाहिए। दूसरे शब्दों में, किसी भी कीमत में बदलाव की अनुमति नहीं थी। निविदाएं खोलने की प्रक्रिया भी निर्धारित की गई। इसके अनुसरण में, बयाना राशि जमा करने वाले कवर-I और तकनीकी-वाणिज्यिक मूल्यांकन वाले कवर-II को खोला गया और निविदाकारों को तकनीकी रूप से योग्य पाया गया। यह पाया गया कि निविदाएं आमंत्रित करने वाले नोटिस में कुछ अस्पष्टता आ गई थी और कुछ कार्यों का दायरा अस्पष्ट या अस्पष्ट बना हुआ था। तकनीकी रूप से योग्य निविदाकारों को चर्चा के लिए बुलाया गया था। सम्मेलन आयोजित किये गये। अंततः, तकनीकी-व्यावसायिक मूल्यांकन के लिए 21.5.1996 को तकनीकी मूल्यांकन समिति की बैठक में सात संशोधनों का सुझाव देने का निर्णय लिया गया। प्रस्तावित संशोधन ओईसीएफ को भेज दिए गए थे। ओईसीएफ ने सुझाव दिया कि बोलीदाताओं को तकनीकी-वाणिज्यिक

मूल्यांकन में सुझाए गए सात पहलुओं तक सख्ती से सीमित मूल्य निहितार्थ प्रस्तुत करने की अनुमति दी जा सकती है और जो बोलीदाता मूल्य भिन्नता खंड को वापस लेने के लिए सहमत हुए हैं, उन्हें इसके लिए सकारात्मक मूल्य निहितार्थ प्रस्तुत करना होगा। यहां यह देखा जा सकता है कि जहां एलएंडटी ने अपनी मूल निविदा के अनुसार एक मजबूत बोली लगाने का दावा किया है, वहीं सुभाष प्रोजेक्ट्स ने मूल्य भिन्नता खंड का सहारा लिया था और अपनी निविदा में सकारात्मक मूल्य निहितार्थ का संकेत नहीं दिया था।

3. सात विचलनों और सम्मेलनों में किए गए कार्यों से संबंधित स्पष्टीकरणों के संबंध में पावर कॉर्पोरेशन द्वारा जारी किए गए संचार के अनुसार, सुभाष प्रोजेक्ट्स ने एक मजबूत बोली लगाई लेकिन अपनी निविदा राशि बढ़ा दी। एलएंडटी ने रुपये की वृद्धि का संकेत दिया। संचार में उल्लिखित सात विचलनों को ध्यान में रखते हुए 35 लाख, लेकिन संकेत दिया कि वह मूल निविदा राशि को रुपये से कम करने को तैयार था। कार्य के बारे में जारी किए गए स्पष्टीकरणों और कार्य के वास्तविक दायरे की उचित समझ को ध्यान में रखते हुए 64 करोड़ रु. इसके बाद मूल्य बोलियां खोली गई। पेश की गई मूल कीमत के अनुसार, एलएंडटी को पांचवें सबसे निचले स्थान पर रखा गया था और सुभाष प्रोजेक्ट्स ने हालांकि मूल निविदा में मूल्य भिन्नता का सहारा लिया था, लेकिन स्पष्टीकरण के बाद उसके द्वारा पेश किए गए फर्म मूल्यांकन के आधार पर उसे सबसे कम बोली लगाने वाला पाया गया। पावर कॉर्पोरेशन द्वारा जारी किया गया पत्र. लेकिन बाद के संचार का जवाब देते समय एल एंड टी द्वारा प्रस्तावित कटौती पर ध्यान देने पर, इसकी बोली सबसे कम पाई गई।

4. निविदाओं का मूल्यांकन निविदा मूल्यांकन समिति द्वारा किया गया। पावर कॉरपोरेशन और ओईसीएफ द्वारा नियुक्त तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा उनकी जांच भी की गई। तीनों के मूल्यांकन के आधार पर, पावर कॉरपोरेशन के स्तर पर यह निर्णय लिया गया कि एलएंडटी अपनी कम

पेशकश के साथ, सबसे कम निविदाकर्ता थी और यह सिफारिश की गई थी कि अनुबंध एलएंडटी को दिया जाए। इस स्तर पर , सुभाष प्रोजेक्ट्स ने केंद्र सरकार में ऊर्जा राज्य मंत्री को व्यक्तिगत रूप से एक पत्र सौंपकर

शिकायत की कि एल एंड टी को सबसे कम निविदाकर्ता के रूप में रखना, इस तथ्य के मद्देनजर उचित नहीं था कि रुपये की कटौती की स्वीकृति इसकी मूल बोली से 64 करोड़ रुपये निविदा शर्तों के विरुद्ध थे और बयाना जमा कवर और तकनीकी-वाणिज्यिक मूल्यांकन प्रस्ताव खोले जाने के बाद इस तरह के किसी भी विचलन की अनुमति नहीं दी जा सकती थी, भले ही मूल्य बोलियां स्वयं नहीं खोली गई थीं। इस पत्र के आधार पर ऊर्जा राज्य मंत्री के एक सचिव की ओर से पावर कॉर्पोरेशन को सुभाष प्रोजेक्ट्स की शिकायत पर गौर करने के लिए पत्र लिखा गया। जब पावर कॉर्पोरेशन अपनी स्थिति पर अड़ा रहा और पश्चिम बंगाल सरकार भी पावर कॉर्पोरेशन के साथ इस बात पर सहमत हो गई कि ठेका एलएंडटी को दिया जाए, जो कि सबसे कम निविदाकर्ता है, तो ऊर्जा राज्य मंत्री और उनका मंत्रालय अपनी मांग पर अड़े रहे। मूल बोलियों के आधार पर एक नया मूल्यांकन किया जाना चाहिए, यहां तक कि उस संबंध में सीधे पश्चिम बंगाल सरकार

को लिखने की हद तक भी जाना चाहिए। अंततः पश्चिम बंगाल सरकार और पावर कॉर्पोरेशन को एलएंडटी द्वारा प्रस्तावित 64 करोड़ रुपये की कटौती की अनदेखी करते हुए नए सिरे से मूल्यांकन करने और सुभाष प्रोजेक्ट्स को अनुबंध देने की सिफारिश करने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस संबंध में सुभाष प्रोजेक्ट्स को पत्र जारी होने पर एलएंडटी ने रिट याचिका के साथ उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। अनुबंध के कामकाज पर कोई रोक नहीं लगाई गई थी, लेकिन उच्च न्यायालय ने सुभाष प्रोजेक्ट्स को काम जारी रखने की अनुमति दी, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि रिट याचिका की अनुमति होने की स्थिति में वह किसी भी इक्विटी का दावा करने का हकदार नहीं होगा। इस प्रकार, रिट याचिका लंबित होने पर, सुभाष प्रोजेक्ट्स ने काम का एक हिस्सा किया, जाहिर तौर पर इक्विटी में किसी भी दावे के

बिना और रिट याचिका के परिणाम के अधीन। हालाँकि, विद्वान एकल न्यायाधीश ने कहा कि, हालाँकि उन्हें इसमें कोई संदेह नहीं था कि पावर कॉरपोरेशन को, बिजली राज्य मंत्री के दबाव के आगे नहीं झुकना चाहिए था, और सुभाष प्रोजेक्ट्स को ठेका देना चाहिए था, लेकिन इसमें हस्तक्षेप करना आवश्यक नहीं था। मामले की विशिष्ट परिस्थितियों में अनुबंध का पुरस्कार, चूंकि अनुबंध वास्तव में सुभाष प्रोजेक्ट्स को दिए जाने से पहले, सुभाष प्रोजेक्ट्स को निविदा राशि को एल एंड टी द्वारा उद्धृत राशि से ठीक नीचे कम करने के लिए राजी किया गया था और यह इसमें शामिल नहीं था। इसमें हस्तक्षेप करना जनहित में है क्योंकि कार्य का एक भाग सुभाष प्रोजेक्ट्स द्वारा पहले ही किया जा चुका है। इस निर्णय को डिवीजन बेंच द्वारा संशोधित किया गया था जिसमें यह भी पाया गया कि सुभाष प्रोजेक्ट्स को अनुबंध का पुरस्कार केंद्रीय ऊर्जा राज्य मंत्री के दबाव में दिया गया था, उस पर अनुचित दबाव था, और हालांकि अनुबंध स्वयं हस्तक्षेप के लिए उत्तरदायी नहीं था, सुभाष प्रोजेक्ट्स, जिसने संदिग्ध तरीकों से अनुबंध हासिल किया था, को उस लाभ का कम से कम एक हिस्सा देने के लिए मजबूर किया जाना था जो उसने अनुबंध पर काम करके अर्जित किया होता। डिवीजन बेंच ने इसका मूल्यांकन एक करोड़ रुपये के रूप में

किया, जो उसने पाया वह सुभाष प्रोजेक्ट्स द्वारा अर्जित मुनाफे के 10 प्रतिशत से कम होगा और इसका भुगतान एल एंड टी को निर्देशित किया गया।

5. अपीलकर्ता-सुभाष प्रोजेक्ट्स के लिए विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा यह तर्क दिया गया था कि उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच ने यह निष्कर्ष निकालने में गलती की थी कि सुभाष प्रोजेक्ट्स को अनुबंध का पुरस्कार

अवैध था और एल एंड टी को अनुबंध का उचित पुरस्कार दिया गया था, इस

मंत्री द्वारा अनुचित रूप से हस्तक्षेप किया गया था और उनके द्वारा इस तरह का हस्तक्षेप अनुचित और अनावश्यक था। विद्वान वकील ने प्रस्तुत

किया कि मंत्री के सचिवालय और मंत्री की टिप्पणियों ने केवल दिशानिर्देशों और मानदंडों का पालन करने का निर्देश दिया था और इस तरह के निर्देश जारी करने को अनुबंध के पुरस्कार के मामले में अनुचित या अनुचित हस्तक्षेप नहीं माना जा सकता है। जनता के प्रतिनिधि के रूप में, सुभाष प्रोजेक्ट्स की ओर से मंत्री को व्यक्तिगत रूप से दिए गए अभ्यावेदन को प्राप्त करने में कुछ भी बाधा नहीं थी और मंत्री द्वारा इसे प्राप्त करने या इसे कार्रवाई के लिए पावर कॉर्पोरेशन को अग्रेषित करने का निर्देश देने में कुछ भी गलत नहीं था। मंत्री द्वारा इस मामले को राज्य सरकार के समक्ष उठाने और उनके द्वारा जारी निर्देशों का पावर कॉरपोरेशन द्वारा पालन कराने के लिए हस्तक्षेप की मांग करने में कुछ भी अनुचित नहीं था। इसके अलावा, मूल रूप से एल एंड टी की पेशकश, सुभाष प्रोजेक्ट्स की तुलना में अधिक थी और यदि एल एंड टी द्वारा रुपये की छूट की पेशकश की गई थी। 64.40 करोड़ रुपये रखे गए, सुभाष प्रोजेक्ट्स को ठेका देने में कोई गड़बड़ी नहीं पाई गई। विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि दिशानिर्देश अनिवार्य थे और उनके खंड 5.03 ने एल एंड टी की कम पेशकश की अस्वीकृति को उचित ठहराया और उस स्थिति में, उच्च न्यायालय का यह निष्कर्ष निकालना उचित नहीं था कि सुभाष प्रोजेक्ट्स को अनुबंध देना उचित नहीं था। एक बार जब यह पाया गया कि सुभाष प्रोजेक्ट्स सबसे कम निविदाकर्ता था और उसे अनुबंध देने का निर्णय लिया गया, तो सुभाष प्रोजेक्ट्स को अपनी पेशकश को एल एंड टी से कम करने की अनुमति देने में कुछ भी अवैध या अनुचित नहीं था। विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि अनुबंध देने के मामले में, उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र सीमित था और ऐसा नहीं था कि उच्च न्यायालय अनुबंध के मूल्यांकन और पुरस्कार पर अपील में बैठा था। इसलिए, उच्च न्यायालय द्वारा सुभाष प्रोजेक्ट्स को इस आधार पर एलएंडटी को मुआवजा देने का निर्देश देने का कोई औचित्य नहीं था कि अनुबंध एलएंडटी को दिया जाना चाहिए था। विशेष रूप से उनसे पूछे गए एक प्रश्न के लिए, उन्होंने कहा है कि मामले के अंत में, यह अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंची कि सुभाष प्रोजेक्ट्स की ओर से प्रस्तुतियाँ

टिकाऊ नहीं हैं, वह पसंद करेंगे कि उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच के फैसले को वैसे ही छोड़ दिया जाए, बजाय इसके कि एलएंडटी द्वारा दायर अपील को स्वीकार करते हुए और सुभाष प्रोजेक्ट्स को दिए गए अनुबंध को रद्द कर दिया गया क्योंकि इस तरह के पाठ्यक्रम को अपनाने से अन्य परिणाम हो सकते हैं जो कि जहां तक सुभाष प्रोजेक्ट्स का संबंध है, अधिक गंभीर होंगे।

6. भारत संघ की ओर से, विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय का यह निष्कर्ष कि केंद्र सरकार में विद्युत राज्य मंत्री द्वारा अनुचित हस्तक्षेप किया गया था, उचित नहीं था। विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि मामले की परिस्थितियों में की गई कड़ी टिप्पणियाँ उचित नहीं हैं। उन्होंने कहा कि मंत्री ने केवल जनहित में काम किया है और इस मामले में उन्हें कोई परेशानी नहीं है। किसी अभ्यावेदन को व्यक्तिगत रूप से प्राप्त करना, या उसे विचार के लिए अग्रेषित करना एक मंत्री, जनता के प्रतिनिधि के लिए अनुचित कार्य नहीं कहा जा सकता है। इस प्रकार, उन्होंने प्रस्तुत किया कि सी.ए. भारत संघ द्वारा दायर 1999 की संख्या 5032, कम से कम केंद्र सरकार में विद्युत राज्य मंत्री और उनके मंत्रालय द्वारा निभाई गई भूमिका के बारे में टिप्पणियों को हटाने की सीमा तक अनुमति देने योग्य थी।

7. एल एंड टी की ओर से, जिसने अपील भी दायर की है सी.ए. 1999 की संख्या 5031, यह प्रस्तुत किया गया था कि यह एक ऐसा मामला था जहां मूल निविदा अधिसूचना स्पष्ट नहीं थी, काम का दायरा सटीक रूप से ज्ञात नहीं था; सम्मेलन आयोजित करने थे, चर्चाएँ करनी थीं, स्पष्टीकरण जारी करना था, कार्य का दायरा परिभाषित करना था और निविदाकारों को कार्य की वास्तविक सीमा और प्रकृति से अवगत कराना था। उस स्थिति में, निविदाकर्ताओं को अपने प्रस्तावों को स्पष्ट करना आवश्यक था, खासकर क्योंकि सुभाष प्रोजेक्ट्स सहित कुछ निविदाकारों द्वारा ठोस प्रस्ताव नहीं दिए गए थे, जिन्होंने मूल्य भिन्नता खंड का सहारा लिया था। उन्होंने

प्रस्तुत किया कि पावर कॉर्पोरेशन, ओईसीएफ और निविदा मूल्यांकन समिति द्वारा नियुक्त सलाहकारों ने सभी प्रासंगिक तथ्यों से अवगत होने पर एलएंडटी और केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण को अनुबंध देने की सिफारिश की थी, वे भी उस दृष्टिकोण से सहमत थे। और राज्य सरकार ने प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की थी और यह केवल केंद्र सरकार में ऊर्जा राज्य मंत्री द्वारा अनुचित और लगातार हस्तक्षेप था, यहां तक कि उचित रूप से मांगे बिना, सभी कारकों से अवगत कराकर उस संबंध में ओईसीएफ की राय भी नहीं ली गई थी। मुद्दे से संबंधित और केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण की राय को ध्यान में रखे बिना, जिसके परिणामस्वरूप अनुबंध सुभाष प्रोजेक्ट्स को दिया गया था और उस स्थिति में, उच्च न्यायालय को सुभाष प्रोजेक्ट्स को दिए गए अनुबंध को रद्द कर देना चाहिए था और एल एंड टी को अनुबंध सौंपने का निर्देश देना चाहिए था। उन्होंने बताया कि खंड 5.03 जिस पर भरोसा किया गया था, उसे छोड़ दिया गया था और मामले में कोई आवेदन नहीं था और अगर किसी को निविदा शर्तों का सख्ती से पालन करना था, तो सुभाष प्रोजेक्ट्स की बोली अस्वीकार करने योग्य थी और निविदा आमंत्रित करने वाले मूल नोटिस की शर्तों के विपरीत, सुभाष प्रोजेक्ट्स को उप-अनुबंध की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए थी या उप-अनुबंध के लिए निर्देशित नहीं किया जाना चाहिए था। उन्होंने बताया कि जहां यह रुख अपनाया गया था कि एलएंडटी द्वारा दी गई कटौती पर ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए, वहीं सुभाष प्रोजेक्ट्स को अपनी पेशकश को एलएंडटी द्वारा प्रस्तावित कटौती से थोड़ा कम करने की अनुमति दी गई थी और यह पूरी कवायद गलत थी। यह केंद्र सरकार में ऊर्जा राज्य मंत्री के कहने पर किया गया था और इस संबंध में की गई कार्रवाई को उच्च न्यायालय ने उचित नहीं पाया है। उन्होंने बताया कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने यह भी माना है कि केंद्र सरकार के ऊर्जा राज्य मंत्री द्वारा पावर कॉर्पोरेशन पर दबाव डाला गया था। उन्होंने कहा कि तार्किक रूप से, सुभाष प्रोजेक्ट्स को ठेका देने को रद्द किया जाना चाहिए और यह निर्देश दिया जाना चाहिए कि ठेका एलएंडटी को दिया जाए। अपील के संबंध में सी.ए. सुभाष प्रोजेक्ट्स द्वारा

दायर 1999 की संख्या 5030 में, विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि किसी भी स्थिति में, उच्च न्यायालय के फैसले में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं था, जिसमें एक राशि दी गई थी, जो कि सुभाष प्रोजेक्ट्स के मुनाफे का 10 प्रतिशत भी नहीं थी। उन्होंने मेसर्स ए.टी. बृज पॉल सिंह एवं अन्य बनाम गुजरात राज्य (1984)4 एससीसी 59 के फैसले का हवाला दिया कि ऐसे मामलों में, लाभ का अनुमान सामान्य रूप से अनुबंध राशि का 15 प्रतिशत लगाया जा सकता है और यहां, उच्च न्यायालय ने एक सकल आंकड़ा लिया था, जो केवल दो था- उसका एक तिहाई.

8. पक्षों द्वारा प्रस्तुत व्यापक पत्राचार और सामग्रियों को विद्वान एकल न्यायाधीश और उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच दोनों द्वारा विज्ञापित और मूल्यांकन किया गया है। उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने वास्तव में पाया कि ओईसीएफ के दिशानिर्देशों के भाग II, खंड 5.03 का उनके द्वारा निर्दिष्ट परिस्थितियों में मामले में कोई अनुप्रयोग नहीं था। उन्होंने यह भी पाया कि समसामयिक दस्तावेजों से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि सभी संबंधित लोग इस आधार पर आगे बढ़े कि दिशानिर्देशों का भाग II, खंड 5.03, लागू नहीं होगा। डिवीजन बेंच ने इस दृष्टिकोण से असहमति नहीं जताई। हमें ऐसा प्रतीत होता है कि निविदाएं आमंत्रित करने के लिए नोटिस जारी करते समय, पावर कॉर्पोरेशन ने टेंडर किए जाने वाले कार्य के दायरे और सीमा को स्पष्ट नहीं किया था। निविदाकारों द्वारा प्रस्ताव दिये गये थे। जाहिर है, काफी भ्रम था और काम के दायरे को स्पष्ट करने और अन्य तकनीकी विवरणों को स्पष्ट करने के लिए स्पष्टीकरण बैठकें और सम्मेलन आयोजित करने पड़े। अंततः सात विचलन भी लिखित रूप में प्रस्तावित किये गये और उन सात भिन्नताओं के आधार पर बोलीदाताओं के प्रस्ताव आमंत्रित किये गये। इसलिए, यह एक ऐसा मामला था जहां काफी भ्रम की स्थिति बनी रही और सुभाष प्रोजेक्ट्स सहित बोलीदाताओं को मूल्य भिन्नता खंड को हटाने सहित नए सिरे से प्रस्ताव देने के लिए मजबूर होना पड़ा। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि जब ये बातचीत चल रही थी तब मूल्य बोलियाँ नहीं खोली गई थीं और

निविदाकारों को स्पष्टीकरण के आलोक में और किए गए सात विचलनों के आलोक में संशोधित प्रस्ताव देने का अवसर दिया गया था। उस अर्थ में, बोलियाँ नहीं खोली गई, क्योंकि संबंधित बोली, मूल्य बोली, अभी भी खोली जानी बाकी है। यदि, उस स्तर पर, निविदाकारों ने कार्य के वास्तविक दायरे और कार्य की विशालता को समझने के बाद, अस्पष्टता द्वारा उत्पन्न भ्रम से उत्पन्न गलत धारणाओं के आधार पर मूल रूप से प्रस्तावित राशि को कम करने की पेशकश की। निविदाएं आमंत्रित करने वाले नोटिस में यह नहीं कहा जा सकता कि ऐसे प्रस्तावों को इस आधार पर खारिज किया जा सकता है कि वे दिशानिर्देशों के खंड 5.03 की शर्तों के विपरीत थे। इस पहलू को विद्वान एकल न्यायाधीश ने भी अपने निर्णय में पाया है। इसलिए, सुभाष प्रोजेक्ट्स की ओर से यह तर्क कि प्रस्तावों में भिन्नता को नजरअंदाज किया जाना चाहिए था, स्वीकार नहीं किया जा सकता। किसी भी स्थिति में, जब पावर कॉरपोरेशन ने अपने सलाहकारों और ओईसीएफ द्वारा नियुक्त स्वतंत्र सलाहकारों से परामर्श करने के बाद और अपनी निविदा मूल्यांकन समिति के मूल्यांकन के आधार पर एल एंड टी को सबसे कम निविदाकर्ता के रूप में रखा, तो मंत्रालय में इसका कोई औचित्य नहीं था। सभी प्रासंगिक तथ्यों से अवगत कराने के बाद ओईसीएफ और केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण से उचित राय प्राप्त किए बिना भी, मामले के तथ्यों पर, राज्य के बिजली विभाग उस पहलू पर जोर दे रहे हैं। इन परिस्थितियों में ऊर्जा राज्य मंत्रालय की जिद और उसका तरीका अजीब लगता है।

9. जहां तक सुभाष प्रोजेक्ट्स का संबंध है, उसे एक ठोस प्रस्ताव देने का अवसर दिया गया था, जो वास्तव में, निविदा आमंत्रित करने वाले नोटिस की शर्तों पर करने के लिए बाध्य था और उसे अपनी कीमत कम करने का भी अवसर दिया गया था। बाद में इसे अनुबंध दिए जाने से पहले, इसके द्वारा इसकी पक्की पेशकश के रूप में उद्धृत किया गया। इसलिए, यह एक ऐसा मामला था जहां किसी भी स्थिति में, सभी निविदाकारों को आमंत्रित किया जाना चाहिए था और सार्वजनिक हित में और परियोजना के हित में उनमें से सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी को स्वीकार

करने से पहले अपनी बोलियां कम करने का अवसर दिया जाना चाहिए था। विद्वान एकल न्यायाधीश ने वास्तव में कहा है, "बदली हुई स्थिति को देखते हुए एक संशोधित बोली भी आवश्यक हो गई है, अर्थात् अनुसूचियों और रेखाचित्रों में परिवर्तन, संशोधन और स्पष्टीकरण, जिसके परिणामस्वरूप भाग के संबंध में विकल्प और संशोधन दोनों हुए हैं- ए यानी सामग्री की आपूर्ति और पार्ट-बी यानी सेवा।" उक्त निष्कर्ष का सुभाष प्रोजेक्ट्स या यूनियन ऑफ इंडिया द्वारा अपनी अपीलों में सफलतापूर्वक विरोध नहीं किया जा सका।

10. इस संदर्भ में उच्च न्यायालय की खंडपीठ इस निष्कर्ष पर पहुंची कि पावर कॉर्पोरेशन के सलाहकार, ओईसीएफ के विदेशी सलाहकार, निविदा मूल्यांकन समिति और केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण का इस निष्कर्ष पर आना उचित था कि संशोधित एल एंड टी की पेशकश सबसे कम थी और उसकी निविदा स्वीकार करने की सिफारिश की गई। इसी परिप्रेक्ष्य में न्यायालय ने यह भी पाया कि राज्य सरकार द्वारा इस अनुशंसा को मंजूरी देना भी उचित था। इस संदर्भ में हमें विद्युत राज्य मंत्री और उनके मंत्रालय के इस रुख पर विचार करना होगा कि खंड 5.03 का पालन किया जाना चाहिए। उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने मंत्रालय से संबंधित रिकॉर्ड मंगवाए और पाया कि संबंधित फाइल कभी भी बिजली मंत्री के समक्ष पेश नहीं की गई थी और इसमें ऐसा कुछ भी नहीं दिखाया गया था कि बिजली राज्य मंत्री को इस तरह का कोई कार्य सौंपा गया हो। मायने रखता है. वास्तव में, डिवीजन बेंच ने पाया कि सार्वजनिक हित को छोड़कर, संबंधित मामला, बिजली राज्य मंत्री के दायरे में भी नहीं हो सकता है। हम उस पहलू में आगे नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन हमें ध्यान देना चाहिए कि ऊर्जा राज्य मंत्रालय ने ओईसीएफ को दस्तावेजों के संदर्भ में पूरे तथ्यों से अवगत नहीं कराया और मामले पर कोई रुख अपनाने से पहले उसकी सलाह नहीं ली। तथ्यों और मामले की परिस्थितियों के आधार पर सबसे कम निविदाकर्ता की पहचान करना। जिस तरह से केंद्र सरकार में ऊर्जा राज्य मंत्री ने इस बारे में काम किया, उसके चलते उच्च न्यायालय की टिप्पणियां सामने

आईं, जिसकी शिकायत केंद्र सरकार ने अपील में की थी। सामग्री के आधार पर, हम यह कहने की स्थिति में नहीं हैं कि उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने जो निष्कर्ष निकाला था, वह उचित नहीं था।

11. मूल्यांकन समिति द्वारा की गई मूल्यांकन प्रक्रिया और अन्य जिम्मेदार निकायों द्वारा व्यक्त की गई राय और उन सामग्रियों के पुनर्मूल्यांकन सहित बड़ी संख्या में दस्तावेजों के माध्यम से हमें विस्तृत रूप से लिया गया, जो विवाद में मामलों पर डिवीजन बेंच के निष्कर्ष का समर्थन करता है। यह देखा जा सकता है कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने भी सुभाष प्रोजेक्ट्स की दलीलों को खारिज कर दिया था, और माना था कि यह समझना मुश्किल है कि पावर कॉरपोरेशन ने सुभाष प्रोजेक्ट्स की निविदा में मूल दोष को कैसे नजरअंदाज कर दिया, जिसमें मूल्य भिन्नता खंड शामिल था और जैसा कि निर्धारित किया गया था, कोई निश्चित कीमत नहीं थी और कैसे उसने केवल मूल्य बोली चरण में इसके साथ बातचीत की, जब सुभाष प्रोजेक्ट्स ने स्वीकार किया कि उसने अपनी बोली कम कर दी ताकि उसकी पेशकश को एल एंड टी की पेशकश के करीब लाया जा सके, इस संबंध में प्रतिबंध के बावजूद। OECF पत्र दिनांक 1.7.1996 ने इसे दिए गए अनुबंध का समर्थन करने के लिए काफी कुछ किया और बताया कि कैसे सुभाष प्रोजेक्ट्स को अन्य ठेकेदारों के साथ उप-अनुबंधों में प्रवेश करने की अनुमति दी गई थी, और वह भी, यहां तक कि सुभाष प्रोजेक्ट्स द्वारा एक समझौते में प्रवेश करने से पहले भी। विद्वान एकल न्यायाधीश ने यह भी पाया था कि किसी भी स्थिति में, निविदा अनुसूची में परिवर्तन, संशोधन और स्पष्टीकरण के मद्देनजर मूल्य भिन्नता आवश्यक हो गई थी। डिवीजन बेंच, कुल मिलाकर, उस निष्कर्ष से सहमत थी। इन निष्कर्षों को रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्रियों पर उचित माना जाता है और इस न्यायालय में इन अपीलों में उन निष्कर्षों में हस्तक्षेप करने का कोई औचित्य नहीं है। इस प्रकार, यह एक ऐसा मामला था जहां विभिन्न चरणों में अलग-अलग मानदंडों का उपयोग किया जा रहा था और जब तक सुभाष प्रोजेक्ट्स को

सबसे कम निविदाकर्ता के रूप में नहीं चुना गया, तब तक बिजली राज्य मंत्रालय द्वारा आपत्तियां उठाने की दृढ़ता अजीब लगती थी।

12. इस प्रकार, हमारे समक्ष प्रस्तुत प्रस्तुतियों के आलोक में प्रासंगिक सामग्रियों के पुनर्मूल्यांकन पर, हम संतुष्ट नहीं हैं कि इन अपीलों में डिवीजन बेंच के फैसले में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता है। चूंकि हम डिवीजन बेंच के इस निष्कर्ष से सहमत हैं कि सुभाष प्रोजेक्ट्स को ठेका देना कानूनी नहीं था, इसलिए हमें एलएंडटी को मुआवजा देने के मामले में डिवीजन बेंच द्वारा अपनाए गए पाठ्यक्रम में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं दिखता है। सुभाष प्रोजेक्ट्स द्वारा देय। हमें तय की गई राशि भी उचित और सुभाष प्रोजेक्ट्स के लिए फायदेमंद लगती है। हम एलएंडटी की अपील पर विचार करने के इच्छुक नहीं हैं कि सुभाष प्रोजेक्ट्स को ठेका दिए जाने को रद्द कर दिया जाए और ठेका एलएंडटी को देने का निर्देश दिया जाए या इसके लिए नए सिरे से निविदा आमंत्रित करने का आदेश दिया जाए। काम। परियोजना की प्रकृति और पहले ही उठाए गए कदमों और इन अपीलों के लंबित रहने के दौरान परियोजना के पूरा होने को देखते हुए, इस तरह के पाठ्यक्रम को अपनाना इन परिस्थितियों में प्रतिकूल होगा।

13. एक पहलू पर विचार करना बाकी है. डिवीजन बेंच ने पावर कॉरपोरेशन को निर्देश दिया था कि वह सुभाष प्रोजेक्ट्स को किए जाने वाले भुगतान में से एलएंडटी को एक करोड़ रुपये का भुगतान करे। इस न्यायालय ने सुभाष प्रोजेक्ट्स द्वारा दायर अपील की विशेष अनुमति की याचिका पर 31.8.1998 को नोटिस जारी करते हुए मुआवजे के भुगतान के संबंध में निर्देश पर रोक लगा दी। इसके बाद, 10.9.1999 को अपील की

अनुमति दी गई। सुभाष प्रोजेक्ट्स के अनुसार, परियोजना पूरी .हो गई थी और भुगतान के लिए अंतिम बिल जमा कर दिया गया था। सुभाष प्रोजेक्ट्स द्वारा एक करोड़ की धनराशि फिक्स डिपोजिट जमा कर उसकी रसीद पावर कॉरपोरेशन को सौंपे बिना पावर कॉरपोरेशन द्वारा भुगतान नहीं

किया गया. इसके बाद, सुभाष प्रोजेक्ट्स ने पावर कॉर्पोरेशन द्वारा रखी गई 1 करोड़ रुपये की सावधि जमा रसीद जारी करने के लिए याचिका दायर की। 8.8.2003 को, इस न्यायालय ने पावर कॉरपोरेशन को सुभाष प्रोजेक्ट्स को सावधि जमा रसीद वापस करने की अनुमति दी, "इस शर्त के अधीन कि सुभाष प्रोजेक्ट्स अपने प्रबंध निदेशक के माध्यम से इस न्यायालय की रजिस्ट्री के समक्ष देय किसी भी राशि को वापस करने के लिए एक उपक्रम निष्पादित करेगा। उपरोक्त अपील को इस न्यायालय द्वारा उस तारीख से चार सप्ताह के भीतर खारिज कर दिया जाएगा।" इस प्रकार, सुभाष प्रोजेक्ट्स को रुपये की सावधि जमा रसीद वापस मिल गई है। सुभाष प्रोजेक्ट्स द्वारा अपने प्रबंध निदेशक के माध्यम से दिए गए वचन के आलोक में 1 करोड़। 8.8.2003 के आदेश के अनुसार और हमारे निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए, सुभाष प्रोजेक्ट्स को रुपये की राशि जमा करने का निर्देश दिया जाना चाहिए। इस न्यायालय में 1 करोड़ रुपये दिए गए, ताकि इसे एल एंड टी को वितरित किया जा सके। सुभाष प्रोजेक्ट्स को उस धन का लाभ मिला है जो उच्च न्यायालय के निर्देशों के आलोक में एल एंड टी को वितरित किया जाना चाहिए था, जो हमने किया है की पुष्टि की। इसलिए, सुभाष प्रोजेक्ट्स को इस राशि के लिए एलएंडटी को कुछ उचित ब्याज देने का निर्देश दिया जाना चाहिए। हमारा मानना है कि इन परिस्थितियों में पांच प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज उचित होगा। इसलिए, हम सुभाष प्रोजेक्ट्स को निर्देश देते हैं कि वह आज से चार सप्ताह के भीतर एक करोड़ रुपये की राशि इस अदालत में 8.8.2003 से जमा करने की तारीख तक पांच प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ जमा कराए। इसके बाद राशि एलएंडटी को वितरित कर दी जाएगी। सुभाष प्रोजेक्ट्स चार सप्ताह के भीतर एलएंडटी को बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से उपरोक्तानुसार ब्याज सहित एक करोड़ रुपये की राशि का भुगतान करने और इस संबंध में एक हलफनामा दाखिल करने के लिए स्वतंत्र होगा। न्यायालय उस तथ्य की गवाही दे रहा है। हलफनामा आज से छह सप्ताह के भीतर दाखिल किया जाना चाहिए. यदि सुभाष प्रोजेक्ट्स रुपये की राशि का भुगतान नहीं करता है। एल एंड टी को आदेशानुसार

ब्याज सहित 1 करोड़ रुपये ड्राफ्ट के माध्यम से या मूल रूप से चार सप्ताह के भीतर इस न्यायालय में जमा करने के आदेश के अनुसार, रुपये की राशि। 1 करोड़ रुपये पर उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच के फैसले की तारीख से उसकी वसूली की तारीख तक प्रति वर्ष 10 प्रतिशत (निर्धारित पांच प्रतिशत प्रति वर्ष के बजाय) की दर से ब्याज लगेगा। एल एंड टी वसूली के लिए इस आदेश को निष्पादित करने की हकदार होगी जैसे कि यह कलकत्ता में संबंधित जिला अदालत के माध्यम से एक डिक्री थी, जो सुभाष प्रोजेक्ट्स की संपत्तियों और इसके निदेशकों की संपत्तियों पर और उनसे व्यक्तिगत रूप से वसूल की गई थी।

14. परिणाम में सी.ए. सुभाष प्रोजेक्ट्स द्वारा दायर सी.ए.1999 की संख्या 5030 को लागत सहित खारिज कर दिया गया है। भारत संघ द्वारा दायर सी.ए.1999 की संख्या 5032 को लागत के संबंध में बिना किसी आदेश के खारिज कर दिया गया है। एल एंड टी द्वारा दायर सी.ए.1999 की संख्या 5031 को भी खारिज कर दिया गया है, ब्याज के प्रावधान और यहां उपर दिये गये अनुसार राशि की वसूली सहीत एक करोड़ रुपये के भुगतान के संबंध में निर्देश के अधीन। इस अपील में भी पक्षकारों को अपना-अपना खर्च उठाना पड़ेगा।

अपीले खारिज

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी गजेंद्र कुमार ¼ आर.जे.एस.½ द्वारा किया गया है।

अस्वीकरणः यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और अधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।